CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

सुमुल डेयरी ने मवेशियों के दूध के खरीद मूल्य में 30 रुपये की बढ़ोतरी की है

अपने इतिहास में सबसे अधिक बढ़ोतरी में, सूरत जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, जिसे आमतौर पर सुमुल डेयरी के रूप में जाना जाता है, ने सूरत और तापी जिलों के डेयरी किसानों से प्रति किलो वसा (गाय और भैंस दोनों) के दूध के खरीद मूल्य में 30 रुपये की वृद्धि की।

इससे किसानों को पहले के 750 रुपये की तुलना में 780 रुपये प्रति किलो वसा वाला गाय का दूध और भैंस के दूध का 810 रुपये प्रति किलो वसा पहले के 780 रुपये की तुलना में मिलेगा।

"यह (मौजूदा बढ़ोतरी) इतिहास में सबसे ज्यादा है। हमारी एक सहकारी समिति है, इसलिए हम दुग्ध उत्पादकों के साथ लाभ साझा करते हैं," सुमुल डेयरी के वरिष्ठ निदेशक जयेश पटेल ने कहा।

सुमुल डेयरी सूरत और तापी जिलों के लगभग 2.5 लाख पंजीकृत दुग्ध उत्पादकों से प्रतिदिन लगभग 14 लाख लीटर दूध खरीदती है।

डिजिटल प्रौद्योगिकियां आंध्र प्रदेश में डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में अत्यधिक योगदान देती हैं, मंत्री अप्पलाराजू कहते हैं

पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री सीदिरी अप्पालाराजू ने ग्लोबल टेक समिट में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी खेती और मत्स्य पालन के क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकों को अपनाने से आंध्र प्रदेश को इन क्षेत्रों को बढ़ावा अवसर पर्याप्त मिला।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गाय-भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान विगत दशकों से किया जा रहा था। हालाँकि, पुरानी प्रक्रियाओं की सफलता दर केवल 28 से 30% है। डिजिटल अनुप्रयोगों की शुरूआत ने सफलता दर में 40% तक सुधार किया है। लिंग छँटाई भी संभव हो गई है और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक मादा बछड़ों का उत्पादन किया जा सकता है।

मंत्री ने कहा कि भ्रूण स्थानांतरण तकनीक को अपनाने से ओंगोल और मुर्रा जैसी नस्लों को बढ़ावा देने में मदद मिली है।

कृषि क्षेत्र को अधिक लाभ दिलाने के लिए युवाओं को योगदान देना चाहिए : तोमर

केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि से जुड़े छात्रों और युवाओं को इस क्षेत्र को और अधिक लाभ पहुंचाने में योगदान देना चाहिए।

चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (सीसीएस-एनआईएएम) में चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रयास कर रही है।

तोमर ने कहा कि इस क्षेत्र में रोजी-रोटी तो है ही, किसानों की देशभक्ति भी है। "कृषि उत्पादन के बिना सब कुछ रुक जाएगा। इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जिन्हें केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर राज्यों के सहयोग से हल करने के लिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।"

डिजिटल पशुधन मिशन का राष्ट्रीय रोल-आउट अप्रैल में संभव

राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (एनडीएलएम) के इस साल अप्रैल तक देश में शुरू होने की उम्मीद है, ताकि भारतीय डेयरी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करने के लिए एक प्रौद्योगिकी सक्षम और किसान-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सके, आर.के. सिंह, सचिव, पशुपालन एवं डेयरी, भारत सरकार ने कहा है।

सिंह ने कहा कि योजना बनाने और रणनीति बनाने के लिए देश के पशुधन धन का एक डिजिटल डेटाबेस बनाने के अलावा, एनडीएलएम किसानों को सेवाओं की डिलीवरी में काफी सुधार करेगा और उन्हें सही समय पर सभी जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। केरल डेयरी विकास विभाग द्वारा आयोजित 'क्षीरा संगमम 2023' के संबंध में हाल ही में यहां आयोजित 'भारतीय डेयरी उद्योग-विजन 2030' पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए।

वक्ताओं ने डेयरी क्षेत्र के विकास निर्माण पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। इस कार्यक्रम का आयोजन मिल्मा, इंडियन डेयरी एसोसिएशन और डेयरी विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री जे. चिनचुरानी ने कहा कि किसानों के लिए स्थिर मूल्य और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमत सुनिश्चित करने में राज्य सरकार और मिल्मा के प्रयास केरल में डेयरी क्षेत्र के विकास के बुनियादी कारक थे।

मुख्य भाषण देते हुए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष, मीनेश सी. शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र के आगे विकास के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है - पशु उत्पादकता में वृद्धि, दूध की गुणवत्ता में वृद्धि, निर्यात दोहन क्षमता, संगठित क्षेत्र को मजबूत करना, और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना।

डॉ. आर.एस. सोढ़ी, अध्यक्ष, इंडियन डेयरी एसोसिएशन, ने कहा कि किसानों द्वारा निर्मित, स्वामित्व और प्रबंधित एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का अस्तित्व, भारतीय डेयरी क्षेत्र की सफलता की कहानी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता था।

के.एस. मिल्मा के अध्यक्ष मणि ने कहा कि यह केरल के लिए गर्व की बात है कि यह डॉ वर्गीज कुरियन का गृह राज्य है, जिन्हें 'मिल्कमैन ऑफ इंडिया' कहा जाता है।

जम्मू और कश्मीर ने टिकाऊ कृषि के लिए 463 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी

अधिकारियों ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी कृषि को एक बड़ा धक्का देते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार ने "जम्मू-कश्मीर में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण" पर एक पांच साल की परियोजना को मंजूरी दी है।

463 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित और समावेशी कृषि-विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों और शिक्षित युवाओं को सशक्त बनाना है।

परियोजना के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक 2,000 किसान खिदमत घर (केकेजी) का निर्माण होगा, जो किसान-उन्मुख सेवाओं के विस्तार के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा।

जम्मू और कश्मीर में विस्तार प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें संरचनात्मक जटिलता और कार्यात्मक विविधता वाले बड़े ग्राहकों की सेवा करना शामिल है। वर्तमान में, विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच 1:1100 के अनुपात और प्रति वर्ष प्रति किसान एक घंटे की संपर्क तीव्रता के साथ एक महत्वपूर्ण अंतर है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन, अटल डुल्लू ने कहा, मौजूदा प्रणाली भी वास्तविक

अगले पृष्ठ पर जारी रखें

दूसरे पेज से जारी

आधार-स्तर की जानकारी की कमी, विस्तार खिलाड़ियों के बीच खराब समन्वय और सामंजस्य और जनता के विश्वास के निम्न स्तर जैसे दोषों से त्रस्त है।

"परियोजना का उद्देश्य कृषि-केंद्रित योजना और संसाधन आवंटन के लिए IoT- सक्षम रीयल-टाइम बिग डेटा का उपयोग करके एक गतिशील कृषि-विस्तार प्रणाली विकसित करके इन मुद्दों को हल करना है। यह प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली एक सक्रिय कृषि विस्तार प्रणाली के लिए आधार बनाएगी। क्लस्टर दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण दी गई कृषि-जलवायु परिस्थितियों के तहत आला कृषि को बढ़ावा देने के लिए जलवायु और कृषि-पारिस्थितिकी जानकारी के वास्तविक समय के क्षेत्रीय विश्लेषण का उपयोग करेगा।"

"जम्मू और कश्मीर में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण" उन 29 परियोजनाओं में से एक है, जिन्हें यूटी में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए यूटी स्तर की शीर्ष समिति द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सहकारी समितियों के माध्यम से फलते-फूलते जैविक खाद्य बाजार में नकदी पर नजर

अनुमानित वैश्विक जैविक खाद्य बाजार लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का है, जहां भारत की हिस्सेदारी 2.7 प्रतिशत है, सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए असीमित अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है, जैविक उत्पादों के लिए उसने एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति की स्थापना की है।

किसानों की आजीविका बढ़ाने और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली पहल, छाता निकाय सहकारी समितियों और अंततः उनके सदस्य किसानों को उच्च कीमत का लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगा। बड़े पैमाने पर एकत्रीकरण, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से जैविक उत्पादों को वहन करने योग्य लागत पर परीक्षण और प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करके।

देश में 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियाँ हैं जिनमें 29 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं। सहकारी क्षेत्र की इस ताकत का उपयोग जैविक समूहों के विकास और इसकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए किया जाएगा।

समाज सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न संबंधित योजनाओं और नीतियों का उपयोग 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के माध्यम से केंद्रित तरीके से करेगा।

3 प्रमुख सहकारी समितियाँ, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF), नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NAFED), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NCCF) और अन्य 3 राष्ट्रीय स्तर के संगठन जैसे, राष्ट्रीय डेयरी इस राष्ट्रीय स्तर की इकाई की स्थापना के लिए विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने हाथ मिलाया है।

इस तरह के छत्र संगठन की आवश्यकता लगातार महसूस की गई है कि भारत, दुनिया में जैविक उत्पादकों की सबसे बड़ी संख्या होने के बावजूद, प्रति उत्पादक कम भूमि और अपर्याप्त उपज के कारण जैविक उत्पाद बाजार में इसका समग्र योगदान उप-इष्टतम है।

वास्तव में, 749 लाख हेक्टेयर भूमि कवरेज के साथ दुनिया भर में लगभग 34 लाख जैविक उत्पादक हैं। दुनिया के कुल जैविक उत्पादकों में से लगभग आधे, 16 लाख भारत के हैं।

एनडीडीबी मिरिडा लिमिटेड ने सिस्तेमा.बायो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और "गोबर से समृद्धि" कार्यक्रम की शुरुआत की

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी मृता लिमिटेड ने भारत की प्रमुख बायोगैस कंपनी सिस्तेमा.बायो के साथ छोटे किसानों के साथ काम करने और कचरे से ऊर्जा बनाने और खुले में टिकाऊ समाधान प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसानों के लिए अतिरिक्त आय पैदा करने के रास्ते।

मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी और एनडीडीबी मृदा लिमिटेड और पीयूष सोहानी, एमडी, सिस्टेमा.बायो इंडिया ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

एनडीडीबी मिरिडा लिमिटेड और सिस्तेमा.बायो संयुक्त रूप से भारत के छोटे और मध्यम डेयरी किसानों के लिए आधुनिक फ्लेक्सी बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए डेयरी सहकारी समितियों, डेयरी संघों, दुग्ध उत्पादक संगठनों और अन्य किसान-केंद्रित संस्थानों के साथ काम करेंगे और इसके बारे में और खाद के बारे में ज्ञान का प्रसार करेंगे। प्रबंधन और बायोस्लरी अनुप्रयोग भी।

यह सहयोगात्मक प्रयास बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देगा और एक मूल्य श्रृंखला तैयार करेगा जो डेयरी किसानों की आजीविका में सुधार करेगा और साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में योगदान देगा और हरित ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। एनडीडीबी के पास ज़कारियापुरा खाद प्रबंधन मॉडल विकसित करते हुए सिस्तेमा बायो के साथ काम करने का प्रत्यक्ष अनुभव है, जो अब गुजरात में गोवर्धन योजना का हिस्सा है।

इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य बायोगैस संयंत्रों के उपयोग के माध्यम से डेयरी किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों की महिला डेयरी किसानों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार करना है। योजना इस वर्ष बायोगैस संयंत्रों के साथ 25,000 से अधिक किसानों तक पहुंचने की है, और आने वाले 2-3 वर्षों में 3,00,000 डेयरी फार्मों की सेवा करने की दृष्टि से है। एनडीडीबी मिरिडा लिमिटेड एंटरप्राइज़ मोड में कृषि के लिए स्लरी-आधारित उत्पादों की बिक्री के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से या जैविक खाद के रूप में उत्पादित बायो-स्लरी के उपयोग को भी बढ़ावा देगा।

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "भारत में डेयरी कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।